जारी किए गए थे कि जब किसी भी काडर के किसी वर्ग विशेष मे व्यक्तियो को अधिशेष घोषित किया जाय तो अधिशेष सूची मे उस वर्ग के अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित आदिम जातियो के कर्मचारियो के नाम तब तक सम्मिलित नही किए जाने चाहिए जब तक कि उक्त ग्रेड मे अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित आदिम जातियो के लिए क्रमश: निश्चित प्रतिशत आरक्षण तक उनकी सख्या न पहुंच गई हो । इन अनदेशो का ध्यान मे रखते हुए किसी भी विभाग/कार्यालय द्वारा किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियो को तब तक अधिशेष घोषित किए जाने का प्रश्न नही उठता जब तक कि सम्बन्धित ग्रेड / काडर मे उनके लिए निर्धारित अनुपात के अनुसार उनकी सख्या पूरी न हो ।

Percentage of Reservations for Backward Classes

5096. SHRI V MAYAVAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state whether Government propose to make reservations upto certain percentage for Backward Classes in Central Government appointments as a measure to bring social equality to them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): Reservations have already been provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services under the Government of India. No classes other than the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been recognised as backward classes by the Government of India for the purpose of reservation in services under it.

Shortfall in use of allocation for 'Right to Work' scheme for Educated Unemployed

5097. SHRI PAMPAN GOWDA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether most of the States have failed to spend the Central allocations under the "right to work" scheme for the educated unemployed; and

(b) if so, the names of such States and the reasons given by them for not using the allocated money?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA): (a) No such programme of 'right to work' for educated unemployed sponsored by Central Government is in operation in States.

(b) Does not arise.

ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये लाइसेंस देना

5098. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रैक्टरो के निर्माण के लिए कितने कारखानो को औद्योगिक लाइसेन्स दिये गये है, और

(ख) उन राज्यो के नाम क्या है जहा ये कारखाने स्थित है और 1973–74 तक कितने ट्रैक्टरो का निर्माण होने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कृषि ट्रैक्टरो के निर्माण करने के लिए 1968 से बाद की अवधि में 12 उद्यमियो को औद्योगिक लाइसेंस दिए गए है ।